सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 92 दर्ज तिथिः—08.02.2024

1. पारस पुत्र गुणेशा
2. सुरेश पुत्र गुणेशा
3. सविता पुत्री गुणेशा
4. गीता पुत्री गुणेशा
5. संजु पुत्री गुणेशा
6. दीपा पुत्र छोगा
7. रवाराम पुत्र नीम्बाराम
8. सकाराम पुत्र नीम्बाराम
9. रूखमों पुत्री नीम्बा
10. भवा पुत्र नीम्बा के कायम मुकाम
    10 / 1 मीरो पत्नी भवा
    10 / 2 देवा पुत्र भवा
    10 / 3 तनु पुत्री भवा
    10 / 4 पार्वती पुत्री भवा
    10 / 5 ममता पुत्री भवा
11. राणा पुत्र माधा
12. रमेश पुत्र माधा
13. सुखदेव पुत्र माधा
14. श्रवण पुत्र माधा
15. राजु पुत्र माधा
16. छोटु पुत्र माधा
17. मदाराम पुत्र करनाराम
18. अशोक पुत्र करनाराम
19. मीरो पुत्री करनाराम
20. मंजु पुत्री करनाराम
21. तीजो पुत्री करनाराम
22. फुसो पुत्री करनाराम
23. पिना पुत्री करनाराम
24. पंखी पुत्री करनाराम

जाति भील निवासी सीलु तहसील गुडामालानी

..................वादी

बनाम

1. गुणेशा पुत्र केवाराम
2. छोगा पुत्र केवा
3. नीम्बा पुत्र केवा
4. माधा पुत्र केवा
5. करना पुत्र केवा
6. सरदाराम पुत्र केवा

जाति भील निवासी सीलू तहसील गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

7. जबरसिंह पुत्र आसुसिंह जाति राजपूत निवासी सिंधासवा चौहान
8. उर्मिला पुत्री भूरचंद
   उषा पत्नी भूरचंद जाति ओसवाल निवासी गुडामालानी

..................असल प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री मोहनलाल विश्नोई
अप्रार्थीः–श्री पूनमाराम विश्नोई
श्री पप्पूराम जाणी

प्रार्थना पत्रः– आदेश–07 नियम–11
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–88, 188 के तहत हाजा न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, मौजा सीलू तहसील गुडामालानी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 06 की पैतृक व संयुक्त खातेदारी आराजी है। उक्त आराजी में से कुछ आराजी का बेचान अन्य प्रतिवादीगण संख्या 07–09 को कर दिया गया है। इस कारण उक्त आराजी के पैतृक होने तथा वादीगण के उक्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत अधिकार निहित होने के कारण खातेदारी अधिकारों की घोषणा तथा प्रतिवादीगण द्वारा किये गए बेचान को वादीगण के हक तक अवैध, शून्य, निष्प्रभावी करवाने का अनुतोष स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण संख्या 07–09 द्वारा उक्त प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

   - कि उक्त आराजी का सहकाश्तकारों के मध्य आपसी सहमति से विभाजन करवाया जाकर पृथक–पृथक खाता कायम किया गया। वादी द्वारा वादी व प्रतिवादी की संयुक्त आराजी खसरा संख्या 434 मौजा भीलों की ढाणी का वाद में जिक्र नहीं किया है। अतः वादी न्यायालय में साफ मंशा से नहीं आने के कारण दावा काबिले–ए–खारिज है।
   - प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 14/1 व खसरा संख्या 10 की भूमि को संपरिवर्तित करवाकर बेचान कर दिया गया है। उक्त संपरिवर्तित भूमि पर वादीगण का कोई हक नहीं होने के कारण दावा काबिले–ए–खारिज है।
   - वादग्रस्त भूमि संपरिवर्तित है। जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर दावा काबिले–ए–खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में उभयपक्षकारान की उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुये प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी खारिज किया जाने का निवेदन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी/अप्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थी/प्रतिवादी का सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाने का निम्न प्रकार निवेदन किया–

- कि वाद वर्णित आराजी में राजस्व अधिकारियों की भूल से वादी का नाम दर्ज नहीं करने के कारण वादी द्वारा अपना हक हिस्सा घोषित करवाने हेतु दावा प्रस्तुत किया है।
- वादी का अन्य आराजी पर हित नहीं होने की वजह से अन्य खसरों का उल्लेख नहीं किया है।
- वादीगण द्वारा बेचान दस्तावेज को चुनौती नहीं दी जाकर घोषणा का दावा किया गया है। बेचान दस्तावेज में वादीगण पक्षकार नहीं है। इसलिए अपने हक हिस्से से अधिक आराजी का बेचान वादीगण के अधिकारों तक शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। साथ ही घोषणा का अधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है एवं दावे को सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही है।
- वाद वर्णित आराजी में संपरिवर्तित भूमि को असंपरिवर्तित भूमि के साथ एकल मानते हुए वादी के घोषणा के अधिकार को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नहीं है एवं दावे को सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही है।

4. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया है। बाद पत्रावली अवलोकन व मनन बहस ज्ञात होता है कि प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के प्रार्थना पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***11. Rejection of plaint.****- The plaint shall be rejected in the following cases:—*
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
> *(e) where it is not filed in duplicate;*
> *(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.*
>
> ***Provided that*** *the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

5. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार हैः–

> While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.

6. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04. 2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैः–

   1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
   2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
   3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नहीं करना।
   4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
   5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
   6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

<u>**Object**</u>

7. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के संपूर्ण विवेचन हेतु न्यायिक दृष्टान्तों का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के <u>**उद्देश्य** (Object)</u> के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519 / 2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07. 2020 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *The underlying object of Order VII Rule 11 (a) is that <u>if in a suit, no cause of action is disclosed, or the suit is barred by limitation under Rule 11 (d), the Court would not permit the plaintiff to unnecessarily protract the proceedings in the suit. In such a case, it would be necessary to put an end to the sham litigation, so that further judicial time is not wasted</u>.*

8. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन याचिका उनवान Azhar Hussain vs Rajiv Gandhi में दिनांक 25.04.1986 को सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *<u>The whole purpose of confernment of such powers is to ensure that a litigation which is meaningless and bound to prove abortive should not be permitted to occupy the time of the court and exercise the mind of the respondent.</u> The sword of Damocle need not be kept hanging over his head unnecessarily without point or purpose. Even in an ordinary civil litigation the Court readily exercises the power to reject a plaint if it does not disclose any cause of action. Or the power to direct the concerned party to strike out unnecessary, scandalous, frivolous or vexatious parts of the pleadings. Or such pleadings*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

> *which are likely to cause embarrassment or delay the fair trial of the action or which is otherwise an abuse of the process of law. An order directing a party to strike out a part of the pleading would result in the termination of the case arising in the context of the said pleading. The Courts in exercise of the powers under the Code of Civil Procedure can also treat any point going to the root of the matter such as one pertaining to jurisdiction or maintainability as a preliminary point and can dismiss a suit without proceeding to record evidence and hear elaborate arguments in the context of such evidence, if the Court is satisfied that the action would terminate in view of the merits of the preliminary point of objection.*

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448 / 2004 उनवान *Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner* में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के उद्देश्य (Object) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The real object of Order VII Rule 11 of the Code is to keep out of courts irresponsible law suits. Therefore, the Order X of the Code is a tool in the hands of the Courts by resorting to which and by searching examination of the party in case the Court is prima facie of the view that the suit is an abuse of the process of the court in the sense that it is a bogus and irresponsible litigation, the jurisdiction under Order VII Rule 11 of the Code can be exercised.*

Role of the Court/Judge

10. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय / न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान T. Arivandandam vs T. V. Satyapal & Another में दिनांक 14.10.1977 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय / न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *The learned Munsif must remember that if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, be should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage. The Penal Code (Ch. XI) is also resourceful enough to meet such men, and must be triggered against them. In this case, the learned Judge to his cost realised what George Bernard Shaw remarked on the assassination of Mahatma Gandhi "It is dangerous to be too good."*

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448 / 2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत न्यायालय / न्यायाधीश की भूमिका (Role of the court/judge) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

> *The trial Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order VII Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X of the Code.*

Material to be considered

12. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519 / 2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के अभिकथनों के पठन (Material to be considered) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.*

Test

13. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9519 / 2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के परीक्षण (Test) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *At this stage, the pleas taken by the defendant in the written statement and application for rejection of the plaint on the merits, would be irrelevant, and cannot be adverted to, or taken into consideration. The test for exercising the power under Order VII Rule 11 is that if the averments made in the plaint are taken in entirety, in conjunction with the documents relied upon, would the same result in a decree being passed.*
>
> *Whether a plaint discloses a cause of action or not is essentially a question of fact. But whether it does or does not must be found out from reading the plaint itself. For the said purpose, the averments made in the plaint in their entirety must be held to be correct. The test is as to whether if the averments made in the plaint are taken to be correct in their entirety, a decree would be passed." In Hardesh Ores (P.) Ltd. v. Hede & Co.5 the Court further held that it is not permissible to cull out a sentence or a passage, and to read it in isolation. It is the substance, and not merely the form, which has to be looked into. The plaint has to be construed as it stands, without addition or subtraction of words.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

How to read and examine the plaint

14. इसी प्रकार सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में न्यायिक दृष्टान्तों उद्धरण यहां प्रासंगिक है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

सिविल अपील 9519 / 2019 उनवान *Dahiben vs Arvindbhai Kalyanji Bhanusali* में दिनांक 09.07.2020 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *<u>If on a meaningful reading of the plaint</u>, it is found that the suit is manifestly vexatious and without any merit, and does not disclose a right to sue, the court would be justified in exercising the power under Order VII Rule 11 CPC. 12.9 The power under Order VII Rule 11 CPC may be exercised by the Court at any stage of the suit, either before registering the plaint, or after issuing summons to the defendant, or before conclusion of the trial, as held by this Court in the judgment of Saleem Bhai v. State of Maharashtra.*
>
> *A three-Judge Bench of this Court in State of Punjab v. Gurdev Singh,13 held that the <u>Court must examine the plaint and determine when the right to sue first accrued to the plaintiff, and whether on the assumed facts</u>, the plaint is within time. The words "right to sue" means the right to seek relief by means of legal proceedings. The right to sue accrues only when the cause of action arises. The suit must be instituted when the right asserted in the suit is infringed, or when there is a clear and unequivocal threat to infringe such right by the defendant against whom the suit is instituted.*

15. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448 / 2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01. 2004 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत वाद पत्र के पठन एवं परीक्षण (How to read and examine the plaint) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *<u>There cannot be any compartmentalization, dissection, segregation and inversions of the language of various paragraphs in the plaint.</u> If such a course is adopted it would run counter to the cardinal canon of interpretation according to which a pleading has to be read as a whole to ascertain its true import. It is not permissible to cull out a sentence or a passage and to read it out of the context in isolation<u>. Although it is the substance and not merely the form that has to be looked into, the pleading has to be construed as it stands without addition or subtraction or words or change of its apparent grammatical sense.</u> The intention of the party concerned is to be gathered primarily from the tenor and terms of his pleadings taken as a whole. <u>At the same time it should be borne in mind that no pedantic approach should be adopted to defeat justice on hair-splitting technicalities.</u>*

Essence

16. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 330 / 2010 उनवान *Ram Kripal Das Ji Charitable Trust vs Phool Chand* में दिनांक 29.02.2012 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के *सारांश* (Essence) को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

> *11.Before dealing with the factual [illegible] the spectrum of Order 7 Rule 11 in the legal ambit needs to be noted. The legal position in regard to Order 7 Rule 11 CPC may be summerised as below:*
>
> *(i) The relevant facts which need to be looked into for deciding an application under Order 7 Rule 11 are the averments made in the plaint. The trial Court can exercise the power at any*

> *stage of the suit-before registering the plaint or after issuing summons to the defendant at any time before the conclusion of the trial. For the purposes of deciding an application under clauses (a) and (d) of Order 7 Rule 11 of the Code, the averments in the plaint are germane; the pleas taken by the defendant in the written statement would be wholly irrelevant at that stage.*
>
> *(ii) The basic question to be decided while dealing with an application filed under Order 7 Rule 11 of the Code is whether a real cause of action has been set out in the plaint or something purely illusory has been stated with a view to get out of Order 7 Rule 11 of the Code.*
>
> *(iii) The Court must remember that if on a meaningful and not formal reading of the plaint it is manifestly vexatious and meritless in the sense of not disclosing a clear right to sue, it should exercise the power under Order 7 Rule 11 of the Code taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. If clever drafting has created the illusion of a cause of action, it has to be nipped in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the Code.*
>
> *(iv) For deciding such an application not any particular plea has to be considered, and the whole plaint has to be read. Only a part of the plaint cannot be rejected and if no cause of action is disclosed, the plaint as a whole must be rejected.*
>
> *(v) Rule 11 of Order 7 CPC lays down an independent remedy made available to the defendant to challenge the maintainability of the suit itself, irrespective of his right to contest the same on merits. The law ostensibly does not contemplate at any stage when the objections can be raised, and also does not say in express terms about the filing of the written statement. Instead, the word "shall" is used, clearly implying thereby that it casts a duty on the court to perform its obligations in rejecting the plaint when the same is hit by any of the infirmities provided in the various clauses of Rule 11, even without intervention of the defendant. Even if no objection is taken by the defendant by filing an application under this provision, the court itself is empowered to reject the plaint if it finds that the case is covered within the four corners of this provision.*
>
> *(vi) It is well settled that the question of jurisdiction namely whether a suit is exclusively triable by a revenue court or a Civil Court can take cognizance of it has to be decided on the allegations made in the plaint. It is also further settled that it is the substance of the plaint and the true nature of the suit that is to be seen to determine the question of jurisdiction. If in substance the relief claimed is one which the revenue court alone is entitled to give, the jurisdiction of the civil court will be ousted even though it may require the revenue court to incidentally determine some ancillary facts. In order to determine the true nature of the relief claimed in a suit, the pith and substance and not the form in which the relief may be couched has to be considered. Each case has to be examined on its own particular facts and no universal rule can be applicable to every case.*

17. प्रकरण में प्रतिवादी / प्रार्थी का अभिकथन है कि विवाद ग्रस्त आराजी के संबंध में यदि कोई बेचान दस्तावेज को चैलेंज करता है तो उसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ना होकर सिविल न्यायालय को है। वादग्रस्त भूमि संपरिवर्तित भूमि है। जिसका सुनवाई का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायालय को नहीं होने के कारण दावा विधि द्वारा वर्जित होने के आधार पर [illegible]बिल–ए–खारिज है। वादी / अप्रार्थी का अभिकथन है कि वाद वर्णित आराज[illegible] स[illegible]वर्तित भूमि को असंपरिवर्तित भूमि के साथ एकल मानते हु[illegible] वादी के घोषण[illegible] अधिकार को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को नहीं होकर राजस्व न्यायालय को है। अतः वादी का दावा विधि द्वारा वर्जित नही है एवं [illegible] को सुनने का क्षैत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

18. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 330 / 2010 उनवान **Ram Kripal Das Ji Charitable Trust vs Phool Chand** में दिनांक 29.02.2012 को दिये गये निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *14. (...) In my view unless a clear finding to that effect is given, the relief claimed by the appellant cannot be granted. <u>Under the provisions of Rajasthan Tenancy Act, declaration and permanent injunction regarding an agricultural land can be granted only by a revenue court. It cannot be disputed that a suit for declaration of tenancy rights regarding an agricultural land has to be filed under Section 88 whereas a suit for permanent injunction has to be filed under Section 188 of the Rajasthan Tenancy Act. Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act provides that all suits of the nature specified in the III Schedule of the Act shall be heard and determined by a revenue court and no court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit. A suit for declaration finds place in Item No.5 whereas suit for permanent injunction finds place in Item No.23 C of the III Schedule. It is thus, very much clear that the present suit was clearly barred by law as Section 207 of the Rajasthan Tenancy Act bars such a suit from being taken cognizance and considered by a court other than a revenue court. The learned trial Court has rightly arrived at a conclusion that the suit is not entertainable by a civil Court.</u>*

19. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1269 / 2019 उनवान **Pyarelal vs Shubhendra Pilania (Minor)** में दिनांक 29.01.2019 को दिये गये निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *10. These submissions fall for our consideration.*
>
> *11.* Section 9 *of the Code of Civil Procedure provides thus:*
>
> ***“9. Courts to try all civil suits unless barred*** *- The Courts shall (subject to the provisions herein contained) have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred.*
>
> *Explanation I - A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies.*
>
> *Explanation ll - For the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in Explanation I or whether or not such office is attached to a particular place.”* Section *9 empowers civil courts to try all suits of a civil nature unless expressly or impliedly barred by any statute.*
>
> *12. Section 256 of the Tenancy Act provides thus:*
>
> ***“256. Bar to jurisdiction of civil courts*** *— (i) Save as otherwise provided specifically in or under this Act, no suit or proceeding shall lie in any civil court with respect to any matter arising under this Act or the rules made thereunder, for which a remedy by way of suit, application, appeal or otherwise is provided therein.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

> *(2) Save as aforesaid no order passed by the State Government or by any revenue court or officer in exercise of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder, shall be liable to be questioned in any civil court." Section 256 bars the jurisdiction of civil courts, save as otherwise provided under the Tenancy Act. Civil courts are expressly barred from trying a suit or proceeding with respect to matters arising under the Tenancy Act or rules made under it for which a remedy by way of a suit, application, appeal or otherwise is provided in the Tenancy Act.*

13. Section 207 of the Tenancy Act provides thus:

> ***"207. Suits and applications cognizable by revenue court only****— (1) All suits and applications of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.*
>
> *(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application.*
>
> *Explanation.— If the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted." Section 207 of the Tenancy Act states that no court other than a revenue court shall take cognizance of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule. Such suits can be heard and determined by a revenue court which has exclusive jurisdiction. The explanation clarifies that if the cause of action is one in respect of which relief may be granted by the revenue court, then it is immaterial that a relief sought from the civil court is greater than, in addition to or not identical to the relief sought from the revenue court. Where a suit is of a nature specified in any of the provisions of the Third Schedule, the bar under Section 256 is attracted and the revenue courts have exclusive jurisdiction to try the suit.*

14. In Bank of Baroda v Moti Bhai4, a two judge Bench of this Court dealt with the question of jurisdiction under Sections 207 and 256 of the Tenancy Act. A bank had sanctioned a demand loan facility to the respondent for which the respondent executed a promissory note and a simple mortgage in favour of the bank. On his failure to repay the loan, the Bank instituted a suit in the civil court for recovery. The respondent raised a preliminary objection that the suit was essentially one for enforcing the mortgage and that the revenue court had the exclusive jurisdiction to entertain the suit by reason of the provisions contained in the Tenancy Act. The Trial court dismissed the objection. Allowing the revision filed by the respondent, the High Court held that that the mortgage deed in respect of agricultural lands formed an essential part of the cause of action. Upon an analysis of Sections 207 and 256 of the Tenancy 4 (1986) 1 SCC 475 [illegible] a two judge Bench of this Court set aside the judgment [illegible] Court with the following reasons:

> *5. A combined reading of these [illegible] sections would show that the jurisdiction of civil courts is barred only in respect of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule to the Act and in respect of suits or applications based on a cause of action in respect of*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

which any relief could be obtained by means of a suit or application of the nature specified in the Third Schedule. The civil court has no jurisdiction to entertain a suit or proceeding with respect to any matter arising under the Act or the Rules made thereunder, provided that a remedy by way of a suit, application or appeal or otherwise is provided in the Act.

A loan given by a Bank to an agriculturist, which is in the nature of a commercial transaction, is outside the contemplation of the Act and can, by no stretch of imagination, be said to be in respect of any matter arising under the Act… The business of the Bank, in so far as lending transactions are concerned, is not to lend moneys on mortgages but the business is to lend moneys.

8. On the question of jurisdiction, one must always have regard to the substance of the matter and not to the form of the suit. If the matter is approached from that point of view, it would be clear that, primarily and basically, the suit filed by the Bank is one for recovering the amount which is due to it from the respondents on the basis of the promissory note executed by respondent 1 and the guarantee given by respondents 2 and 3." (Emphasis supplied) Section 207 read with Section 256 of the Tenancy Act bars the jurisdiction of the civil courts in respect of suits and applications of the nature specified in the Third Schedule to the Act. The question before us is whether the relief claimed by the appellant can be granted exclusively by a revenue court under the provisions of the Tenancy Act.

15. Section 88 of the Tenancy Act provides thus:

*"**88. Suits for declaration of right:-** (1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.*
(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant. (4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person."

Sl. No. 5 of the Third Schedule provides thus:

"THE THIRD SCHEDULE Suits, Applications and Appeals under the Act (See Sections 207, 214, 215 & 217) S. Section Description of suit, application or Period of Time Proper Court/ No. of Act appeal limitation from Court Fees Officer which competent period to dispose begins to of run

"THE THIRD SCHEDULE
Suits, Applications and Appeals under the Act
(See Sections 207, 214, 215 & 217)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

S.No.	Section of Act	Description of suit, application or appeal	Period of limitation	Time from which period begins to run	Proper Court Fees	Court/Officer competent to dispose of

5.	88	Suit for declaration of the plaintiffs right :- (i) as a tenant, or (ii) as a tenant of khudkasht, or (iii) as a sub-tenant, or (iv) for a share in a joint tenancy		None	One rupee	Assistant Collector

Sl. No. 5 in the Third Schedule read with Section 207 of the Tenancy Act stipulates that a suit for the declaration of a right provided in Section 88 would lie before a revenue court. In a suit where the relief sought for is the declaration of the right stipulated in Section 88, Sections 207 and 256 read with the Third Schedule bar the jurisdiction of civil courts and vest jurisdiction exclusively with a revenue court.

16. It is admitted that the suit property is agricultural property and the appellant has filed a suit before the revenue court for the declaration of his khatedari rights.

18. The appellant has prayed that the gift deed dated 10 February, 2011 be declared void to the extent of the share claimed by the appellant and that respondent Nos. 1 to 5 be restrained from alienating the share of the appellant. The civil court may decree the relief prayed only if it is first determined that the appellant is entitled to khatedari rights in the suit property. Under the provisions of the Tenancy Act, the jurisdiction to declare khatedari rights vests exclusively with the revenue courts. Only after such determination may the civil court proceed to decree the relief as prayed. The explanation to Section 207 clarifies that if the cause of action in respect of which relief is sought can be granted only by the revenue court, then it is immaterial that the relief asked from the civil court is greater than, or in addition to or not identical with the relief which the revenue court would have granted. In view of this matter, the civil court may not grant relief until the khatedari rights of the appellant have been decreed by a revenue court.

19. A claimant whose khatedari rights have been decreed by a revenue court is however on a different footing from a claimant whose khatedari rights are pending adjudication by a revenue court. Where the khatedari rights are yet to be decreed, a claimant must first approach the revenue courts. The relief to declare the gift deed void and to restrain respondents Nos. 1 to 5 from interfering with or alienating the property vesting in a civil court may be sought for in a suit by a claimant in whom khatedari rights have been decreed by a revenue court.

20. उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 1269/2019 उनवान **Pyarelal vs Shubhendra Pilania (Minor)** में दिनांक 29.01.2019 को दिये गये निर्णय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 एवं धारा–256 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत आने वाले समस्त मामलों को सुनने का एकमात्र क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालयों में निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

21. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रथम अपील 286/2014 उनवान **Smt. Sua Devi vs Sharvan Ram And Ors** में दिनांक 25.01.

2021 को दिये गये निर्णय में संपरिवर्तित भूमि पर राजस्व न्यायालय एवं सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

Provisions of <u>Section 207</u> of the Act, 1955 reads as under:

> ***"207. Suits and applications cognizable by revenue court only--*** *(1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a revenue court.*
> *(2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application."*

The provision confers jurisdiction on revenue courts qua suits and application of the nature specified in the Third Schedule attached to the Act, 1955. <u>The Third Schedule inter alia prescribes suit, application or appeal of various descriptions which can be filed under the Act, 1955 in relation to agricultural lands.</u>

The jurisdiction of the court/authority has to be determined based on the status of the subject matter as it exists on the date of filing of the suit, as in case the determination is to be made based on nature of land as per the document in question, the very fact that the entire land in question already stands converted to non-agriculture purposes and as noticed, from a bare reading of provisions of Section 207 of the Act, 1955 it is apparent that ***<u>the jurisdiction of the revenue courts is confined to dealing with the suits pertaining to agriculture land, the same would amount to conferring jurisdiction on revenue court, qua a subject matter i.e. converted land, which it does not have.</u>***

The trial court, as quoted hereinbefore, when confronted with the said aspect pertaining to conversion of land into residential, merely referred to the fact that the order of conversion could be challenged by way of appeal and that the civil court had no jurisdiction to cancel the order of conversion. The observation made by the trial court while dealing with the said aspect about maintainability of the suit in a case where the land stood converted on the date of filing of the suit is wholly besides the point inasmuch as the submissions made did not pertain to challenge to the conversion, the same pertained to the effect of conversion on the jurisdiction of the court and as such, the observations made and finding recorded by the trial court in this regard cannot be sustained.

In view of the above discussions, as per the plaint averments, the entire land which was comprised in the sale deed under challenge stood converted from agriculture to residential purposes way back in the year 2006 and the suit was filed in the year 2014 ***<u>it cannot be said that the jurisdiction of civil court qua the said land was barred under the provisions of Section 207 of the Act, 1955 and as such rejection of the plaint by the trial court as barred by law cannot be sustained and matter deserves to be remanded back to the trial court.</u>***

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

22. इस संबंध में विधिमान्य न्यायिक सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि संपरिवर्तित भूमि के संबंध में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 207 सपठित धारा 256 के तहत राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः [illegible] का दावा विधि द्वारा वर्जित है एवं दावे को सुनने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को ही है। अतः ऐसे दावे सिविल

प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के उपबन्ध–डी के तहत विधि द्वारा वर्जित हैं।

23. इस संबंध में वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रथम अपील 286 / 2014 उनवान *Smt. Sua Devi vs Sharvan Ram And Ors* में दिनांक 25. 01.2021 को दिये गये निर्णय पर अपने अभिवचनों को आधारित किया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि संपरिवर्तित भूमि के संबंध में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 से पठित धारा–256 के तहत राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत वादी के विपरीत होकर प्रकरण में सटीक चस्पा होता है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण पैरा संख्या–32 में दिया गया है।

24. इस संबंध में वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन 137 / 2015 उनवान *Hasti Cement Pvt. Ltd. & Anr vs Sandeep Charan & Ors* में दिनांक 07.03.2018 को दिये गये निर्णय पर अपने अभिवचनों को आधारित किया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रकरण में कृषि भूमि पर किये गये बेचाननामा को निरस्त करने, स्वामित्व व घोषणा के लिए वाद पर सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के विरूद्ध निगरानी के निर्णयन का प्रश्न निहित था। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी पर किये गए बेचान को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विवादित आराजी पर किये गए बेचान को निरस्त करने का अनुतोष के संबंध में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 से पठित धारा–256 के तहत राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत विवादित आराजी पर किये गए बेचान को निरस्त करने का अनुतोष से संबंधित होने के कारण प्रकरण में सटीक चस्पा नहीं होता है। उक्त प्रकरण प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *The issue which arises in the present case essentially pertains to the jurisdiction of the civil court to deal with the suits pertaining to cancellation of an instrument pertaining to agricultural land on account of the fact that under the provisions of Section 207 of the Tenancy Act, the suits and applications which could be heard and determined by a revenue court are barred before other courts.*
>
> *From what has been noticed hereinbefore, it can be safely concluded that if the allegation in the plaint/substance of the allegations in the plaint allege the instrument to be void and no cancellation is required and without seeking such cancellation the relief of declaration pertaining to tenancy rights with regard to the agricultural land in question can be obtained by the plaintiff, only the revenue courts would have jurisdiction to deal with the subject matter of the suit and consequently the jurisdiction of civil courts would be barred. <u>However, if the allegations made in the plaint make out a case of document being voidable, relief of cancellation of such a voidable document can only be granted by civil court and irrespective of the fact that the instrument pertains to agricultural land, the suit would not be barred under Section 207 of the Tenancy Act.</u> Therefore, the trial court in each case, where a issue in this regard is raised, based on the stage of the suit i.e. either based on the plaint averments or as per evidence available on record would have to come to a conclusion as to whether the facts as alleged, if established or as established in a case where evidence has been led makes the instrument void or voidable and decide accordingly.*
>
> *The fact that even in a case of a void instrument a relief of declaration in this regard has been sought, as laid down in the case of Rukmani (supra) once the declaration about status of Tenancy rights is granted,*

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

the consequential relief to the effect that the instrument in question is void and ineffective can always be granted by the revenue court.

25. इस संबंध में वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीसन 4945 / 2008 उनवान *Smt Prabhati Devi vs Balu And Ors* में दिनांक 13. 05.2011 को दिये गये निर्णय पर अपने अभिवचनों को आधारित किया है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत वाद में वाद का अवमूल्यन करने व वादहेतुक से संबंधित होने एवं हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार से संबंधित नहीं होने के कारण प्रकरण में सटीक चस्पा नहीं होता है।

26. इस संबंध में वादी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिवीजन 88 / 2017 उनवान *Gagandeep Kaur v. Paramjeet Kuar* में दिनांक 24.07.2018 को दिये गये निर्णय पर अपने अभिवचनों को आधारित किया है। उक्त प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रकरण में कृषि भूमि पर किये गये बेचाननामा को निरस्त करने, स्वामित्व व घोषणा के लिए वाद पर सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने के विरूद्ध निगरानी के निर्णयन का प्रश्न निहित था। उक्त प्रकरण में विवादित आराजी पर किये गए बेचान को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया था। प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विवादित आराजी पर किये गए बेचान को निरस्त करने का अनुतोष के संबंध में वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–207 से पठित धारा–256 के तहत राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत विवादित आराजी पर किये गए बेचान को निरस्त करने का अनुतोष से संबंधित होने तथा संपरिवर्तित आराजी से संबंधित नहीं होने के कारण प्रकरण में सटीक चस्पा नहीं होता है। उक्त प्रकरण प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः–

5. The issued raised by the petitioners in the present revision petition is squarely covered by judgment of this Court in Hasti Cement Pvt. Ltd. & Anr. v. Sandeep Charan & Ors.: S.B. Civil Revision Petition No.137/2015, decided on 07.03.2018, wherein after taking into consideration the law on the subject, it was laid down that in a case where a plaint was filed seeking cancellation of the sale deed on account of the fact that the suit property in question was ancestral and transfer was made without any reason, basis or necessity, the transaction was only voidable and not void and, therefore, the suit was maintainable before the civil courts.

सत्यमेव जयते

27. इसी प्रकार वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा अपील संख्या 6457–6458 / 2011 उनवान *Ugam Bai Vs Manohar Lal* में दिनांक 01.11.2023 को दिये गये निर्णय पर अपने अभिवचनों को आधारित किया है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रकरण में कृषि भूमि पूर्व में निर्णित प्रकरण के पश्चात उसी आराजी पर पुनः नया दावा लाया गया। नये दावे में रेस–ज्यूडिकेटा के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित बताते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि रेस–ज्यूडिकेटा के आधार पर प्रकरण में प्राथमिक विवाद्यक तय करते हुए साक्ष्य सबूत के आधार पर वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के [illegible] निर्णय किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त परिस्थिति [illegible] संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत रेस–ज्यूडिकेटा से [illegible] होने तथा संपरिवर्तित आराजी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested

संबंधित नहीं होने के कारण प्रकरण में सटीक चस्पा नहीं होता है। उक्त प्रकरण प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार हैः—

> *उपरोक्त सभी विधिक दृष्टांतों के आधार विवादित भूमि के कृषि से अकृषि उपयोग और गैर कृषि संपरिवर्तन किये जाने व उसके आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद वर्जित होने के लिए उभयपक्ष की संबंधित लिखित दस्तावेजीय साक्ष्य ली जानी आवश्यक है। उसके पश्चात साक्ष्य के उपरांत ही इस बाबत् सही विधिक स्थिति की पुष्टि होने पर ही विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। (....)*

28. प्रकरण में उक्त आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत दावे में लिखित आराजी संपरिवर्तित आराजी होने के आधार पर हाजा राजस्व न्यायालय का सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण दावा विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रथम अपील 286/2014 उनवान *Smt. Sua Devi vs Sharvan Ram And Ors* में दिनांक 25.01.2021 को दिये गये निर्णय द्वारा ऐसा अभिमत प्रतिपादित किया गया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 448/2004 उनवान Sopan Sukhdeo Sable & Ors vs Assistant Charity Commissioner में दिनांक 23.01.2004 में स्पष्ट किया है कि दावे के सारगर्भित पठन से अगर कोई दावा में चतुराई पूर्वक अभिवचनों के प्रारूप को तैयार किया जाकर आभासी वादहेतुक उत्पन्न करना प्रतीत हो तो दावे को शुरूआत में खारिज किया जाना चाहिए।

29. इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में उक्त आधार पर दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत प्रकरण में वाद वर्णित आराजी के संपरिवर्तित आराजी होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। अतः उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत नही होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—7 नियम—11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर स्वीकार जाकर वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज 26.12.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.07 20:25:18 IST
Reason: SelfAttested